

## उपायुक्त प्रवीण कुमार

# काम काज में जीरो, मजमेबाजी में हीरो

फरीदाबाद (म.मो.) दिनांक 2 मई सोमवार के दिन जिले भर के हरियाणा सरकारी दफ्तरों में कोई अफसर नहीं बैठ पाया, दूर-दूर से आने वाले लोग सरकार को कोसते व गालियां बकते वापस लौट रहे थे। कारण यह था कि उपायुक्त डा0 प्रवीण कुमार ने तमाम अफसरों को स्टाफ सहित बल्लभगढ़ अनाज मंडी में एकत्र करके मजमा लगा रखा था। उपायुक्त ने इस मजमें में शामिल होने का आदेश तो केंद्र सरकार (टेलिफोन भविष्य निधि इएसआई आदि) के अधिकारियों को भी दिए थे लेकिन उन्होंने इन आदेशों को रद्दी की टोकरी में फेंक कर अपने-अपने कार्यालयों में ही सुचारू रूप से कार्य किया।



इस मजमें का नाम दिया गया था प्रशासन आपके द्वार 1 जो निष्काम प्रशासन अपने दफ्तरों में बैठ कर आने वाली जनता का काम नहीं निपटा सकता वह भला सड़क के किनारे एवं अनाज मंडी में बैठकर क्या कार्य निपटाएगा? और यदि कार्यालयों की बजाए इस तरह के मजमों में ही प्रशासन बढ़िया काम करता है तो फिर दफ्तरों की इमारतें बनवाने व उनके रख रखाव पर अरबों रुपया क्यों बर्बाद किया जाता है? क्यों नहीं तमाम दफ्तरों का कार्य इस तरह के मजमों से ही चलाया जाता?

जिस जगह पर मजमा लगाया गया था। उसके आस-पास गंदा पानी मल मूत्र व अन्य कूड़े-कचड़े के ढेर सड़ रहे थे।

थे बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए, उनके तो फार्म तक भी उपलब्ध नहीं थे इस मजमें में, वन विभाग द्वारा जो पौध बरसात के मौसम में बांटी जाती है, उसे डीसी के आदेश पर उस मजमें में बांटा जा रहा था। आधे से अधिक लोगों ने तो पौधे ले कर आसपास फेंक दिए, शेष जिन्होंने घर जा कर इन पौधों को लगाने का प्रयास किया भी होगा तो उनका इस मौसम में सफल होना कठिन है। पौधों की इस बर्बादी का परिणाम यह होगा कि पौधारोपण के उचित समय पर पौधों का अभाव रहेगा।

उपायुक्त ने कुछ वरिष्ठ अफसरों को उनके असल काम से हटा कर खरीदारी करने दिल्ली भेज रखा था। उनके जिम्मे बच्चों को बांटने के लिए कपड़े व उपहार आदि लाना था ये उपहार मजमें की समाप्ति के बाद बांटे गए थे। इतना ही नहीं मजमें में आने वाली जनता जनार्दन के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गयी थी। भंडारे के इस प्रसाद में खीर, पूरी, सब्जी, आदि की व्यवस्था की गयी थी। अफसरों व स्टाफ के लिए भोजन की व्यवस्था वहीं पर थोड़ा अलग से की गई थी। इस तरह का भंडारा गत माह ग्रीन फील्ड कालोनी के निकट दयाल नगर में भी लगाया गया था। यहां 20000 लोगों के लिए खिचड़ी बनाई गयी थी जिसे खाने केवल 400 बच्चे ही पहुंचे। बाकी बची खिचड़ी को वहां प्रबंधन में लगे तमाम जिले के अफसरों के वाहनों में शेष पेज 2 पर

## पानी चोरों ने डीसी को दिखाया ठेगा

फरीदाबाद (म.मो.) डीसी प्रवीण कुमार के आदेश पर एसडीएम प्रदीप गोदारा ने सेक्टर 28 स्थित नगर निगम के एक ट्यूबवैल पर छापा मार कर पानी भरते 6 टेंकरों को मौके पर पकड़ा और थाना सैक्टर- 31 पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने नाम चारे को भा.द.सं. की धारा 430, 379 व 188 के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन आगे न तो कोई कार्यवाही की और न ही करनी है। क्योंकि इनमें से 2 टेंकर एक पूर्व पार्षद के तथा 2 निगम कर्मियों के बताये गये। डीसी द्वारा की गयी इस कार्यवाही के विरोध में चोरी करने तथा कराने वाले सभी संगठित हो कर सामने आ खड़े हुए। चशमदीद जानकार बताते हैं कि नगर निगम आयुक्त ने डीसी के सामने ही एसडीएम को हड़काया कि उन्होंने उसके अधिकार क्षेत्र में छापा मारा कैसे? यदि छापे मारने का इतना ही शौक है तो वे उनकी तैनाती निगम में करवा देते हैं। डीसी ने बहुत कहा कि वह डीसी है और उसको छापे लगवाने का अधिकार है परन्तु निगमायुक्त के नेतृत्व में मौजूद अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी।

## व्यापारियों ने संगठित शक्ति से झुकायी सरकार

फरीदाबाद (म.मो.) जो सरकार शहर के दुकानदारों से घरों में दुकाने चलाने के नाम पर 6 से 10 हजार रू. प्रति वर्ग गज की दर से मांग रही थी वही सरकार अब सीधे 500 से 1000 रू. प्रति वर्ग गज की दर से राजी होने जा रही है। पहले तो सरकार ने अपनी गुंडागर्दी के दम पर इस प्रस्ताव को नगर निगम के सदन में आने से ही रोका परन्तु जब शहरवासियों के दबाव के चलते जुझारू पार्षद इसे सदन में ले ही आए तो उसे पास करना ही पड़ा सदन द्वारा पारित यह प्रस्ताव अब हरियाणा सरकार की स्वीकृति हेतु चंडीगढ़ भेजा गया है। इस सरकार में इतनी ताकत नहीं कि जनता की संगठित शक्ति के बल पर पारित प्रस्ताव को स्वीकृत न करे। क्योंकि सरकार ताकत की भाषा को खूब अच्छे से समझती है जिसकी बानगी उसने पिछले दिनों व्यापारियों के धरने व प्रदर्शनों में देख ली है।

## विकास की बलिवेदी पर चढते किसान

# राजनेताओं को मिला खेल का मैदान

**नो** एडा (म.मो.) पूंजीवादी विकास के नाम पर किसानों से लगातार छीनी जा रही अति उपजाऊ जमीन ने 7-8 मई को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इसमें 3 किसान और 2 किसानी छोड़कर पुलिस बने जवान मारे गए। सरकार द्वारा किसानों से जमीन छीनने को लेकर हुआ यह संघर्ष न तो पहला है और न आखरी। उत्तर प्रदेश के गांव भट्टा, परसौल से लेकर टप्पल, अलीगढ़, मथुरा व आगरा तक के किसान सरकार की इस छीना झपटी के विरोध में गत 4 माह से शान्तिपूर्ण धरने व प्रदर्शन कर रहे थे। परन्तु सरकार के क्रान पर जूं तक नहीं रेंगी। किसानों ने अपनी आवाज बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए 7 मई को जब परिवहन विभाग के तीन कर्मचारियों को बंधक बना लिया तो सरकार पूरी गुंडागर्दी पर उतर आई।



पुलिस ने जब उन पर लाठी व गोली चलाई तो जवाब में किसानों ने भी लाठी गोली चलाई जिसकी आशा पुलिस को नहीं थी। पुलिस मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। लेकिन पुलिस ने पुनर्गठित हो कर ग्रामीणों पर जो हमला किया वह अत्यन्त हृदय विदारक रहा। इस हमले ने राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपनी-अपनी राजनीति खेलने का मैदान उपलब्ध करा दिया। सभी पार्टियां अपने-अपने अंदाज में ग्रामीणों को बहकाने व अपना वोट बैंक बनाने की जुगत में लगी हैं। जो कांग्रेस यहां घड़ियाली आंसू बहा रही है वही कांग्रेसी सरकार हरियाणा व महाराष्ट्र के जैतापुर में इससे कुछ अलग तो नहीं कर रही। मुलायम या